अध्याय-V

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

5.1 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रणालीगत कमियों को उजागर किया गया।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एक योजना के रूप में कानूनी और संस्थागत मजबूती की नींव पर आधारित है, जिसे जिला खनिज संस्थान न्यास के विवेकपूर्ण प्रबंधन द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसे परियोजना निष्पादन के माध्यम से लागू किया जाता है और प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से लक्षित लाभों को प्राप्त करती है।

हमने पाया कि योजना के संशोधित दिशानिर्देशों को अधिसूचित करते समय, राज्य शासन ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 से लेखापरीक्षा प्रावधान को शामिल नहीं किया, जिसमें कहा गया है कि जिला खनिज संस्थान न्यास खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की समय-सारणी के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए। यह राज्य को संशोधित दिशानिर्देशों में परिकल्पित आश्वासन स्तर से दूर ले जाता है।

हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 से छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में विचलन का उल्लेख किया, जो खनन प्रभावित समुदायों के लिए संभावित रूप से इच्छित लाभों को कम कर रहा है। देखे गए प्रमुख मुद्दों में 'प्रभावित व्यक्तियों' की परिभाषा में संशोधन और विशिष्ट चयन मानदंडों के बिना लोगों को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार शामिल था। प्रभावित व्यक्तियों के लिए निधियां स्पष्ट मानदंड स्थापित किए बिना या लक्षित हितग्राहियों की पहचान किए बिना वितरित की जा रही थीं। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 में निर्धारित राज्य विधानसभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रावधान को भी नियमों से हटा दिया गया था।

राज्य मुख्य खनिजों के लिए रॉयल्टी के साथ-साथ जिला खनिज संस्थान के अंशदान के समय पर भुगतान की सुविधा के लिए खनिजऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करता है। हालांकि, गौण खनिजों के लिए इसी तरह की समान व्यवस्था की कमी थी और गौण खनिजों के लिए पारगमन पास हस्तलिखित रूप से जारी किए गए थे जो रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान भुगतान सुनिश्चित नहीं करते थे। इससे योजना के कार्यान्वयन की संस्थागत व्यवस्था में एक कमी रह जाती है।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिलों में गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, जहां वार्षिक योजना/बजट तैयार किए बिना न्यास निधि का उपयोग किया गया और भारत सरकार के आदेशों के विपरीत, राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ को अंतरित कर दिया गया, जबकि प्रकोष्ठ के पास बकाया राशि थी। न्यासों ने ऑटो-स्वीप या फ्लेक्सी जमा का विकल्प चुने बिना धनराशि

को बचत खातों में रखा, जिससे ब्याज से होने वाली आय को अधिकतम करने के अवसरों से वंचित रह गए।

न्यास की स्थापना के बाद पांच से 65 महीनों की देरी से 'प्रभावित क्षेत्रों' की पहचान की गई और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने से पहले ही कार्यों के लिए ₹1,060.70 करोड़ आवंटित कर दी गई। इसके अलावा, जिला कलेक्टरों द्वारा 'प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों' के तहत पहचाने गए गांवों की सूची अधिसूचित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, न्यास द्वारा धनराशि का 81 प्रतिशत उपयोग किए जाने के बावजूद, चयनित 11 जिलों में से 44 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव इसमें शामिल नहीं हो पाए। न्यास निधि का उपयोग अयोग्य क्षेत्रों जैसे स्वागत द्वारों का निर्माण, कलेक्ट्रेट परिसर में उद्यान, विभागीय कार्यालय भवनों का नवीनीकरण/निर्माण, कार्यालय वस्तुओं का क्रय, कार्यालय उपयोग के लिए वाहनों का क्रय, निजी शिक्षण संस्थानों को अनुदान आदि के लिए भी किया जा रहा था। विभिन्न मामलों में क्रय में अनुशासन की कमी को भी देखा गया। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रय दस्तावेजों को खुली फाइलों में रखा गया था। न्यासों में कुशल मानव संसाधन का अभाव था और प्रमुख पदों को नहीं भरा गया था।

निगरानी के पहलू के सबंध में, राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने निर्धारित दस्तावेजीकरण और अभिलेखों के रखरखाव को सुनिश्चित नहीं किया और अनिवार्य आवृत्तियों पर बैठकें आयोजित करने में विफल रही। प्रमुख जानकारियाँ वेबसाइट पर प्रकट/अद्यतन नहीं की गयी थी। न्यास के कार्यों/गतिविधियों की सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी।

वैधानिक और संस्थागत ढ़ांचे, निधियों का प्रबंधन, कार्य का निष्पादन और योजना की निगरानी में पायी गयी कमियों ने इच्छित प्रभाव को कम कर दिया, जो कि जिला खनिज संस्थान संग्रह में दूसरे सबसे बड़े स्थान पर रहने वाले राज्य के लिए बहुत महत्व रखता है।

5.2 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार:

- ***'प्रभावित व्यक्तियों' की सूची तुरंत तैयार करें और छत्तीसगढ़ राजपत्र में 'प्रभावित क्षेत्रों' के साथ इसे अधिसूचित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लक्षित हितग्राहियों तक पहुंचें।***
- ***खनन प्रभावित क्षेत्रों में संसाधनों के समान वितरण के लिए प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों का कवरेज सुनिश्चित करना।***
- ***एक दीर्घकालिक मास्टर प्लान और विजन दस्तावेज तैयार करें जो गतिविधियों को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्यों के अनुरूप संरेखित करे और जिसका क्रियान्वयन खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे।***
- ***वित्तीय अनुशासन के लिए शासी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित न्यासों द्वारा वार्षिक योजना और बजट की तैयारी करना सुनिश्चित करें।***

- *सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन में जिला खनिज संस्थान न्यास की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने की योजना बनाएं।*
- *यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करें कि जिला खनिज संस्थान न्यास और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सहित कानूनी ढ़ांचे और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुसार काम कर रहे हैं।*

रायपुर
दिनांक: 06 मई 2026

(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 13 मई 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक